संख्या-289/2026/130के-2/22-3-2026-17(111)/26

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी पुत्र श्री नरेन्द्र, निवासी जनपद-गाजियाबाद की फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4400/प्रो0अनु0(7)/14/2025(बैठक दिनांक 19-01-2026), दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी (बंदी संख्या-537/2025) पुत्र श्री नरेन्द्र, जो खोडा कालोनी, थाना-खोडा, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। दिनांक 10-10-2014 को बंदी द्वारा वादी मुकदमा की 12-13 वर्षीय नाबालिग लड़की को सामान रखने के बहाने कमरे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-33/2015 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट सं0-2, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 31-07-2025 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-376(2)(1), 342 के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा दिनांक 31-08-2025 तक 07 वर्ष, 02 माह, 21 दिन की अपरिहार व 07 वर्ष, 02 माह, 27 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में रखना आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई में समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी पुत्र श्री नरेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी (बंदी संख्या-537/2025) पुत्र श्री नरेन्द्र, निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-130(1)के-2/22-3-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-289/2026/130के-2/22-3-2026-17(111)/26

दिनांक 22 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी (बंदी संख्या-537/2025) पुत्र श्री नरेन्द्र, जो खोडा कालोनी, थाना-खोडा, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। दिनांक 10-10-2014 को बंदी द्वारा वादी मुकदमा की 12-13 वर्षीय नाबालिग लड़की को सामान रखने के बहाने कमरे में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-33/2015 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट सं0-2, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 31-07-2025 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-376(2)(1), 342 के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। रजिस्टर नं0-1 के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 29 वर्ष है तथा बंदी द्वारा दिनांक 31-08-2025 तक 07 वर्ष, 02 माह, 21 दिन की अपरिहार व 07 वर्ष, 02 माह, 27 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा पुन: अपराध कारित करने की संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में रखना आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई में समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता/जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अमित उर्फ टोनी पुत्र श्री नरेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in